



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार 19 नवम्बर, 2016 / 28 कार्तिक, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग-ख

अधिसूचना

शिमला-2, 17 नवम्बर, 2016

संख्या: जीएडी-बी-(ए) 1-11/2013-1(मण्डी).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए पटवार वृत्तों से समाविष्ट, जिला मण्डी में एक नई उप-तहसील कटौला का सृजन किया जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील कटौला, जिसका मुख्यालय कटौला में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं :-

उप-तहसील का नाम	उप-मण्डल का नाम	तहसील का नाम	जिला	मुख्यालय	सम्मिलित पटवार वृत्त	तहसील का नाम जिससे अपवर्जित किए
1	2	3	4	5	6	7
कटौला	सदर मण्डी	सदर मण्डी	मण्डी	कटौला	1. सेगली 2. कटौला 3. कमान्द 4. नमलाये 5. बथेरी	सदर मण्डी पधर

आदेश द्वारा,
वी०सी० फारका,
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification NO. GADB-(A)-1-11/2013-1 (Mandi) Dated 17-11-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Section-B

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th November, 2016

No. GAD-B-(A)-1-11/2013-1(Mandi).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Tehsil Kataula in District Mandi may be created comprising of the Patwar Circles shown in column 6 below to, provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them and to have the better administrative control.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil at Kataula with its headquarter at Kataula in District Mandi, Himachal Pradesh with immediate effect:--

Name of the Sub-Tehsil	Name of Sub-Division	Name of Tehsil	District	Head-quarter	Patwar Circles Included	Name of Tehsil from where excluded
1	2	3	4	5	6	7
Kataula	Sadar Mandi	Sadar Mandi	Mandi	Kataula	1. Segli 2. Kataula	Sadar Mandi

					3. Kamand 4. Namlay 5. Batheri	Padhar
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--------

By order,
V.C. PHARKA,
Chief Secretary.

ख-अनुभाग

અધિસૂચના

शिमला-2, 17 नवम्बर, 2016

संख्या: जीएडी-बी-(ए) 1-6/2008-(बिलासपुर).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में उपमण्डल (नागरिक) घुमारवीं से तहसील झण्डूता और उप तहसील कलोल को अपवर्जित करके उप मण्डल (नागरिक) झण्डूता के नाम से ज्ञात एक नए उप-मण्डल (नागरिक) का सृजन किया जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 160) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, उपमण्डल (नागरिक) घुमारवीं से 12 पटवार वृत्तों वाली तहसील झण्डूता और 8 पटवार वृत्तों वाली उप तहसील कलोल के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपवर्जित करते हैं और जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में एक नए उप-मण्डल (नागरिक) झण्डूता, जिसका मुख्यालय झण्डूता में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं, जिनमें निम्नलिखित पटवार वृत्त समाविष्ट होंगे :—

[illegible]

			14. सलवाड 15. जेजवीं 16. कलोल 17. भडोली कलां 18. घराण 19. कोठी 20. नघ्यार	
--	--	--	---	--

आदेश द्वारा,
वी०सी० फारका,
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification NO. GAB-(A)-1-6/2008 (Bilaspur) Dated 17-11-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th November, 2016

No. GAD-B-(A)-1-6/2008 (Bilaspur).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Division (Civil) to be known as Sub-Division (Civil) Jhanduta in District Bilaspur, Himachal Pradesh may be created by excluding Tehsil Jhanduta and Sub Tehsil Kalol from Sub Division (C) Ghumarwin to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them and to have the better administrative control.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) read with sub-section (3) of Section-7 of the Code of Criminal Procedure 1973, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh is pleased to exclude the entire area of Tehsil Jhanduta having 12 Patwar Circle and Sub Tehsil Kalol having 8 Patwar Circle from Sub Division (C) Ghumarwin and to create a new Sub-Division (Civil) Jhanduta with its headquarter at Jhanduta, in District Bilaspur, Himachal Pradesh, which shall consist of the following Patwar Circles with immediate effect :--

Name of Sub Division	District	Head-quarter	Patwar Circles Included	Name of Tehsil/ Sub Tehsil from where excluded
Jhanduta	Bilaspur	Jhanduta	1. Changar Talai 2. Balsina 3. Badagaon	Tehsil Jhanduta Sub Tehsil Kalol

			4. Sunhari 5. Samoh 6. Gehrhavi 7. Jangla 8. Samleta 9. Nakhalehda 10. Dahad 11. Behran 12. Jhanduta 13. Dhani 14. Salawad 15. Jejvi 16. Kalol 17. Bhadoli Kalan 18. Ghararh 19. Koti 20. Naghyar	
--	--	--	---	--

By order,
V.C. PHARKA,
Chief Secretary.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 नवम्बर, 2016

संख्या: ई.एक्स.एन.-एफ(1)-3/2012.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 74) की धारा 13 की उप धारा(3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: 14-31/68 ई एण्ड टी, तारीख 3 मार्च, 1970 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 26-03-1970 को प्रकाशित सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) रूलज, 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) संशोधन रूलज, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 6 का संशोधन.—सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) रूलज, 1970 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के रूल 6 में—

(क) शीर्षक में " 'c' and 'f' and certificates in forms 'D', 'E-I'. And 'E-II'. " चिन्हों, अक्षरों और शब्दों का लोप किया जाएगा।;

(ख) सब रूल (6)में "Form- 'C' or 'F' " शब्दों, चिन्हों, और अक्षरों के पश्चात् " or Form 'H' or Form-'I' or certificate पद Form 'E-I' or 'E-II' " शब्द, चिन्ह और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

और

(ग) सब रूल (10) के स्थान पर निम्नलिखित सब रूल रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(10) The Commissioner may by notification in the Official Gazette, declare that declarations in forms 'C' and 'F' or Form 'H' or 'I' or certificate in Form 'E-I' or 'E-II' prescribed under the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, of a particular series, design or colour or in cases mentioned in sub-rules (2) and (3) of rule 6-B shall be deemed as obsolete and invalid with effect from such date as may be specified in the notification |" |

3. रूल 6-बी का संशोधन.—उक्त नियम के रूल 6-बी में,—रूल 6-बी के उपबन्धों को सब रूल (1) के रूप में पुनर्संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्याकित सब रूल (1) के पश्चात् निम्नलिखित सब रूल (2) और (3) अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(2) Where any dealer, after the generation of declaration in Form ‘C’ or ‘F’ or ‘H’ or ‘I’ or certificate in Form ‘E-I’ or ‘E-II’, as the case may be, discovers that he has filled in incorrect particulars or any other information at the time of generating the declaration/certificate mentioned above, and intends to rectify the same, he shall submit an application online to his assessing authority within six months from the date of generation of such declaration/certificate mentioning therein the incorrect particulars or any other information furnished by him, which he wants to rectify and the correct particulars or any other information in respect thereof. Such application shall be accompanied with a printed copy of such declaration/certificate, alongwith an undertaking in Form ‘GG’ mentioning the Form ‘C’ or ‘F’ or ‘H’ or ‘I’ or certificate in Form ‘E-I’ or ‘E-II’ which has not been generated through the official website of the Department. The Assessing Authority on finding the application in order shall recommend the cancellation of such forms and reissuance of fresh forms as requested to the Zonal Collector for approval of the request.

(3)Where any dealer has generated declaration in Form ‘C’ or ‘F’ or ‘H’ or ‘I’ or certificate in Form ‘E-I’ or ‘E-II’ by misrepresentation of facts or by fraud or in contravention of the provisions of the Central Sales Tax Act, 1956 and rules made thereunder, the Assessing Authority or any officer authorized by the Commissioner, after affording such dealer a reasonable opportunity of being heard cancel such declaration Form(s) or Certificate(s), and the list of declaration Form(s) or Certificate(s) so cancelled shall be uploaded on the official website of the Department. The declaration Form(s) so cancelled shall be deemed to have not been generated through the official web-site of the Department |" |

4. नए फार्म जी जी का अन्तःस्थापन.—विद्यमान फार्म एन डी के पश्चात् निम्नलिखित नया फार्म अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" FORM GG

FORM OF INDEMNITY BOND

[See rule 6-B(2)]

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT [I, _____
S/o , _____ registered dealer under the Central Sales Tax Act, 1956 under
registration No. _____ dated _____ in the State of _____/[We/M/s
_____/a firm / a company registered under the laws of India and having its

registered office at registered dealers under the Central Sales Tax Act, 1956 under registration No _____ in the State of Himachal Pradesh _____].

(hereinafter called the Obligor) '[is]/ are} held and firmly bound under the Governor of Himachal Pradesh _____ (hereinafter called the Government) in the sum of _____ (Rupees (in words) _____) well and truly to be paid to the Government on demand and without demur for which payment to be well and truly made I bind myself and my heirs, executors, administrators, legal representatives and assigns [we bind ourselves our successors and assigns and the persons for the time being having control over our assets and affairs],

Signed this _____ day of _____ two thousand _____

WHEREAS sub-rule (2) of rule 6-B of the Central Sales Tax Himachal Pradesh Rules, 1970 requires that in the event a dealer has generated an incorrect form on account of filing of erroneous data the purchasing dealer and as the case may be also a selling dealer each to furnish an indemnity bond to, in the case of purchasing dealer, the notified authority from whom the said form was obtained and in the case of a selling dealer, the notified authority of his State.

AND WHEREAS the Obligor herein is such [purchasing] dealer [selling] dealer.

AND WHEREAS the Obligor has generated an incorrect declaration in Form 'C' or Form 'F' or Form 'H' or Form-'I' or certificate in Form 'E-I' or 'E-II ' bearing No. which was blank duly completed], and was issued to him by _____ (name and designation of the authority) which was issued to him by _____ (name and designation of the authority)] and sent to, (selling dealer) [received by him from _____ (name of the purchasing dealer)] and sent to _____ (notified authority of the selling dealer's State) in respect of the goods mentioned below (hereinafter referred to as the 'Form').

Sl. No	No. of Bill/ Invoice/	Challan Date	Description of Goods	Quantity	Amount
--------	-----------------------	--------------	----------------------	----------	--------

NOW the conditions of the above written bond or obligation is such that the Obligor shall in the event of a loss suffered by the Government (in respect of which the decision of the Government or the authority appointed for the purpose shall be final and binding on the Obligor) as a result of the misuse of the Form, pay to the Government on demand and without demur the said sum of Rs _____ Rupee _____ (in words) and shall otherwise indemnify and keep the Government harmless and indemnified against and from all liabilities incurred by the Government as a result of the misuse of such Form. THEN the above written bond or obligation shall be void and of no effect but otherwise shall remain in full force, effect and virtue. The obligor further undertakes to mortgage/charge the properties specified in the Schedule hereunder written by execution of proper deed of mortgage/charge for the payment of the said sum [whenever called upon to do so by the assessing authority.]

SCHEDULE

(Give details of properties mortgaged/charged)

AND THESE PRESENTS ALSO WITNESSETH THAT the liability of the Obligor hereunder shall not be impaired or /discharged by reason of any forbearance, act or omission of the Government or for any time being granted or indulgence shown by the Government, or by reason of any change in the [constitution of the Obligor in cases where the Obligor is not an individual.

The Government agrees to bear the stamp duty, if any chargeable on these presents.

IN WITNESS WHEREOF the Obligor "has set his hand / "has caused these] presents executed by its authorized representatives, on the day, month and year above written.

Signed by the above named Obligor In presence of :

1.

2.

(Obligor's signature)

Accepted for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh by name and designation of the Officer duly authorized in pursuance of Article 299(1) of the Constitution, to accept the bond for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh.

In presence of –

Name and Designation of the Officer

* Strike out which is not applicable. | " |

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(1)-3/2012 dated 17/11/2016 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th November, 2016

No.EXN-F(1)-3/2012.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No.74 of 1956), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Central Sales Tax Himachal Pradesh Rules, 1970, notified vide this Department Notification No. 14-31/68 E&T, dated 3rd March, 1970 and published in the Rajptra, Himachal Pradesh dated 26.3.1970, namely:--

1. Short title and commencement.—(1.) These rules may be called the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajptra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 6.— (1) In rule 6 of the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970 (hereinafter referred to as the 'said rules'),--

(a) in the heading, the signs, letters and words " 'C' and 'F' and certificates in forms 'D', 'E-I.' And 'E-II' " shall be omitted. ;

- (b) in sub-rule (6) after the signs, words and letters "Form- 'C' or 'F' ", the words, signs and letters or Form 'H' or Form-'I' or certificate in Form 'E-I' 'E-II' " shall be inserted.; and
- (c) for sub-rule(10), the following sub-rule shall be substituted, namely:--

"(10) The Commissioner may by notification in the Official Gazette, declare that declarations in forms 'C' and 'F' or Form 'H' or 'I' or certificate in Form 'E-I' or 'E-II' prescribed under the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, of a particular series, design or colour or in cases mentioned in sub-rules (2) and (3) of rule 6-B shall be deemed as obsolete and invalid with effect from such date as may be specified in the notification."

3. Amendment of rule 6-B.—(1) In rule 6-B of the said rule,—

the provisions of rule 6-B shall be renumbered as sub-rule (1) and after sub-rule(1) as so renumbered, the following new sub-rules (2) and (3) shall be inserted, namely:--

“(2) Where any dealer, after the generation of declaration in Form ‘C’ or ‘F’ or ‘H’ or ‘I’ or certificate in Form 'E-I' or 'E-II', as the case may be, discovers that he has filled in incorrect particulars or any other information at the time of generating the declaration/certificate mentioned above, and intends to rectify the same, he shall submit an application online to his assessing authority within six months from the date of generation of such declaration/ certificate mentioning therein the incorrect particulars or any other information furnished by him, which he wants to rectify and the correct particulars or any other information in respect thereof. Such application shall be accompanied with a printed copy of such declaration/certificate, alongwith an undertaking in Form ‘GG’ mentioning the Form ‘C’ or ‘F’ or ‘H’ or I’ or certificate in Form 'E-I' or 'E-II' which has not been generated through the official website of the Department. The Assessing Authority on finding the application in order shall recommend the cancellation of such forms and reissuance of fresh forms as requested to the Zonal Collector for approval of the request.

(3)Where any dealer has generated declaration in Form ‘C’ or ‘F’ or ‘H’ or 'I' or certificate in Form 'E-I' or 'E-II' by misrepresentation of facts or by fraud or in contravention of the provisions of the Central Sales Tax Act, 1956 and rules made thereunder, the Assessing Authority or any officer authorized by the Commissioner, after affording such dealer a reasonable opportunity of being heard cancel such declaration Form(s) or Certificate(s), and the list of declaration Form(s) or Certificate(s) so cancelled shall be uploaded on the official website of the Department. The declaration Form(s) so cancelled shall be deemed to have not been generated through the official web-site of the Department."

4. Insertion of new Form GG.—After the existing Form ND, the following new Form shall be inserted, namely:--

" FORM GG
FORM OF INDEMNITY BOND
[See rule 6-B(2)]

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT 'I, _____
S/o , _____ registered dealer under the Central Sales Tax Act, 1956 under

registration No. _____ dated _____ in the State of _____ / [We/M/s _____ / a firm / a company registered under the laws of India and having its registered office at registered dealers under the Central Sales Tax Act, 1956 under registration No _____ in the State of Himachal Pradesh _____]

(hereinafter called the Obligor) '[is]/ are} held and firmly bound under the Governor of Himachal Pradesh _____ (hereinafter called the Government) in the sum of _____ (Rupees (in words) _____) well and truly to be paid to the Government on demand and without demur for which payment to be well and truly made I bind myself and my heirs, executors, administrators, legal representatives and assigns [we bind ourselves our successors and assigns and the persons for the time being having control over our assets and affairs],

Signed this _____ day of _____ two thousand _____

WHEREAS sub-rule (2) of rule 6-B of the Central Sales Tax Himachal Pradesh Rules, 1970 requires that in the event a dealer has generated an incorrect form on account of filing of erroneous data the purchasing dealer and as the case may be also a selling dealer each to furnish an indemnity bond to, in the case of purchasing dealer, the notified authority from whom the said form was obtained and in the case of a selling dealer, the notified authority of his State.

AND WHEREAS the Obligor herein is such [purchasing] dealer [selling] dealer.

AND WHEREAS the Obligor has generated an incorrect declaration in Form 'C' or Form 'F' or Form 'H' or Form 'I' or certificate in Form 'E-I' or 'E-II' bearing No. which was blank duly completed], and was issued to him by _____ (name and designation of the authority) which was issued to him by _____ (name and designation of the authority)] and sent to, (selling dealer) [received by him from _____ (name of the purchasing dealer)] and sent to _____ (notified authority of the selling dealer's State) in respect of the goods mentioned below (hereinafter referred to as the 'Form').

Sl. No	No. of Bill/ Invoice/	Challan Date	Description of Goods	Quantity	Amount
--------	-----------------------	--------------	----------------------	----------	--------

NOW the conditions of the above written bond or obligation is such that the Obligor shall in the event of a loss suffered by the Government (in respect of which the decision of the Government or the authority appointed for the purpose shall be final and binding on the Obligor) as a result of the misuse of the Form, pay to the Government on demand and without demur the said sum of Rs _____ Rupee _____ (in words) and shall otherwise indemnify and keep the Government harmless and indemnified against and from all liabilities incurred by the Government as a result of the misuse of such Form. THEN the above written bond or obligation shall be void and of no effect but otherwise shall remain in full force, effect and virtue. The obligor further undertakes to mortgage/charge the properties specified in the Schedule hereunder written by execution of proper deed of mortgage/charge for the payment of the said sum [whenever called upon to do so by the assessing authority.]

SCHEDULE

(Give details of properties mortgaged/charged)

AND THESE PRESENTS ALSO WITNESSETH THAT the liability of the Obligor hereunder shall not be impaired or /discharged by reason of any forbearance, act or omission of the

Government or for any time being granted or indulgence shown by the Government, or by reason of any change in the [constitution of the Obligor in cases where the Obligor is not an individual.

The Government agrees to bear the stamp duty, if any chargeable on these presents.

IN WITNESS WHEREOF the Obligor "has set his hand / "has caused these] presents executed by its authorized representatives, on the day, month and year above written.

Signed by the above named Obligor In presence of :

1.

2.

(Obligor's signature)

Accepted for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh by name and designation of the Officer duly authorized in pursuance of Article 299(1) of the Constitution, to accept the bond for and on behalf of the Governor of Himachal Pradesh.

In presence of –

Name and Designation of the Officer

* Strike out which is not applicable. '

By order,
Sd/-
Principal Secretary (E&T).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th November, 2016

No. TPT-F (1)-3/2015-I.—In continuation of this department Notification No. Tpt-F(1)-3/2015 dated 20-02-2016, the Governor, Himachal Pradesh in pursuance of the powers conferred under clause (iii) of proviso to sub rule (1) of rule 108 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 and all other powers enabling him in this behalf, is pleased to allow the use of “Amber Light with Flasher” upon top front of the official vehicle of **Political Advisor to the Chief Minister, H.P.**, within his jurisdiction. This notification will be effective from the date of publication in H.P. Rajpatra.

By order
NARINDER CHAUHAN
Additional Chief Secretary (Transport).

श्रम एवं रोजगार विभाग**अधिसूचना**

शिमला-171002, 18 नवम्बर, 2016

संख्या श्रम (ए) 4-1/2014-बी.ओ.सी.डब्ल्यू.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेषज्ञता समिति के परामर्श के पश्चात्, अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-6/2007-बी.ओ.सी.डब्ल्यू तारीख 4 दिसम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 263 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2008 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है) के नियम 263 में,—

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (हि0प्र0से0) के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति या सैकेण्डमेंट के आधार पर बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगा, ऐसा न होने पर श्रम एवं रोजगार विभाग के किसी अधिकारी, जो उप श्रमायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, को बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।” और

(ख) उप-नियम (2) के खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) अपेक्षानुसार इसके कार्यकलापों की देखरेख के लिए, श्रम विभाग में श्रम अधिकारियों के समतुल्य वेतनमान के श्रम कल्याण अधिकारियों की, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा की किसी भी शाखा में स्नातक की अनिवार्य अर्हता के पश्चात् व्यवसाय प्रबन्ध निष्णात (एम0बी0ए0) भी हो:

परन्तु पच्चीस प्रतिशत पद श्रम निरीक्षकों में से भरे जाएंगे जिनकी संवर्ग में कम से कम दस वर्ष की सेवा हो और जिनके लिए केवल स्नातक की अर्हता अनिवार्य होगी; और

3. नए नियम 286(क) और 286(ख) का अन्तःस्थापन.—उक्त नियमों के नियम 286 के पश्चात् निम्नलिखित नए नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“286(क) कल्याण उपायों का क्रियान्वयन.—राज्य सरकार अधिनियम की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी भी कल्याण उपाय के क्रियान्वयन के लिए निर्देश दे सकेगी।

286(ख) कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना.—बोर्ड, कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकेगा तथा हिताधिकारियों, हिताधिकारी का/की पति या पत्नी और

उसके दो बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक अवसंरचना का सृजन कर सकेगा। बोर्ड ऐसे संस्थानों को चलाने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और इस निमित्त अपनाए जाने वाले अन्य तौर-तरीके प्रकल्पित कर सकेगा।”।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2014-BOCW dated 18-11-2016 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 18th November, 2016

No. Shram (A) 4-1/2014-BOCW.—In exercise of the powers conferred by section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, the Governor, Himachal Pradesh, after consultation with the Expert Committee is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 notified *vide* Notification No. Shram (A) 4-6/2007- BOCW, dated 4th December, 2008 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, on 08-12-2008, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 263.—In rule 263 of the Himachal Pradesh Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 (herein-after referred to as the ‘said rules’,—

(a) for sub rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) The Board may, with the prior concurrence of the Government, appoint an officer of HPAS to be posted on deputation/secondment basis, failing which, an officer not below the rank of Dy. Labour Commissioner of the Department of Labour & Employment will be posted as Secretary of the Board.; and

(b) in sub-rule (2), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

“(i) Labour Welfare Officers in the pay scale equivalent to those of the Labour Officers in the Labour Department as per requirement to look after its affairs with essential qualifications as Graduation in any discipline followed with Master of Business Administration from any recognized University:

Provided that 25% of the posts shall be filled up from amongst Labour Inspectors with minimum ten years of service in the cadre for whom only graduation will be an essential qualification”.

3. Insertion of new rules 286-(A) and 286-(B).—After rule 286 of the ‘said rules’, the following new rules shall be inserted, namely:—

“286-(A) Implementation of welfare measures.-The State Government, while exercising the power conferred by section 62 of the Act, may direct the Board for implementation of any welfare measures.

286-(B) Establishment of Skill Development institute.-The Board may construct Skill Development Training Institute and create necessary infrastructure to impart training to the beneficiaries, spouse and two children of the beneficiaries. The Board may also devise the training courses for running such institutions and other modalities to be followed in this behalf.”.

By order,

Sd/-

Principal Secretary (Labour & Employment).